IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

विश्व समाज में लोकतान्त्रिक विमर्श और डिजिटल तकनीक की चुनौतियाँ

नीरज कुमार राय

सहायक प्रोफेसर,समाजशास्त्र

राजकीय महिला महाविद्यालय, ढिंढुई, पट्टी,प्रतापगढ़

सारांश : वर्ष दो हजार के प्रारंभ से लेकर 2010 के दौरान 'डिजिटल लोकतंत्र' या 'ई-लोकतंत्र' जैसी अवधारणाएं स्पष्ट कह रही थीं कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां किस तरह से लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं, और परिणामस्वरूप इसके भीतर शासन-प्रक्रिया से नागरिकों को जोड़ने की भरपूर संभावना है । यह विचार अरब क्रांति के दौरान साकार रूप में दिखाई पड़ा, जहां सोशल मीडिया नागरिकों को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित समाज शास्त्रीय विश्लेषण हैं ।

मुख्य शब्द : ट्वीटर क्रांति, डिजिटल लोकतंत्र, डिजिटल तानाशाही, डिजिटल क्षेत्र, डिजिटल सहयोग

वॉशिंगटन टाइम्स ने ईरान में 2009 के राष्ट्रपति चुनावों के बाद बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के लिए ट्वीटर क्रांति शब्द का प्रयोग करते हुए अपने संपादकीय में लिखा, "आखिरकार स्वतंत्रता की भावना तेहरान के फ्रीडम स्क्वायर पहुंची । यह तकनीकी आशावाद अब फीका पड़ चुका है। जैसा कि ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व ने आंदोलन को कुचल डाला । वहीं जिन डिजिटल उपकरणों के माध्यम से यह आंदोलन संगठित हुआ था, उसका उपयोग लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने के लिए तानाशाहों और लोकतांत्रिक नेताओं द्वारा समान रूप से किया जाने लगा । 2021 में डिजिटल लोकतंत्र एक नए अवतार में सामने आया, जिसने 'डिजिटल अधिनायकवाद' के विरुद्ध लोकतांत्रिक देशों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया। डिजिटल अधिनायकवाद इंटरनेट का एक ऐसा रूप है, जो राज्यों को राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव जैसे अस्पष्ट कारणों के बहाने मनमाने ढंग से किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने का अधिकार देता है। यह नागरिकों की व्यापक निगरानी के साथ-साथ "साइबर सेना ", संगठित और राज्य-प्रायोजित समूहों जैसे तंत्रों को सक्षम बनाता है, जो कुछ और नहीं सेंसरशिप के नए तरीके हैं। इनके ज़रिए सोशल मीडिया खातों यानी किसी की डिजिटल उपस्थिति पर सामूहिक हमला किया जाता है, और व्यक्तियों और समुदायों को परेशान किया जाता है। इस मॉडल की आंतरिक संरचना के मुकाबले इसका एक बाहरी ढांचा भी है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमज़ोर करना चाहता है। डिजिटल तानाशाही कथित रूप से

बड़ी तेज़ी से ऑनलाइन दुनिया से आगे बढ़कर बुनियादी भौतिक आधारभूत संरचनाओं को अपने घेरे में ले रही है, जिसके माध्यम से इंटरनेट संचालित होता है। (1,2,3,4)

पिछले एक साल में जी7, क्वॉड जैसे मौजूदा समूहों और कोपेनहेगन डेमोक्रेसी समिट, फोरम 2000, फ्रीडम ऑनलाइन कांफ्रेंस एवं अन्य मंचों पर देखा कि लोकतांत्रिक देशों को डिजिटल तानाशाही के उभरते ख़तरे से लोकतंत्र को "बचाने" के लिए एकजुट होने का आह्वान किया जा रहा है। इन बहसों में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, मीडिया स्वतंत्रता, डिजिटल साक्षरता, और इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़े बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने सहित कई मुद्दे शामिल थे। इन सबके बावजूद, लोकतांत्रिक परंपराएं ऐतिहासिक कारणों और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर बात करें तो दक्षिण कोरिया का सार्वजनिक आधिकारिक चुनाव अधिनियम 1994 में हुए लोकतांत्रिक संक्रमण और उस दौरान अशांत राजनीतिक वातावरण का शेष है। उसके बाद के दशकों में इस अधिनियम में ऑनलाइन चुनावी कवरेज को लेकर बने दिशा-निर्देशों को जोड़ा गया और ऐसी सामग्रियों को प्रतिबंधित किया गया, जो चुनाव नतीजों को प्रभावित कर सकती हैं। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च न्यायालय भी चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर आक्रामक या भ्रामक जानकारियों से भरे वक्तव्यों को जारी करने को अपराध घोषित करता है।

मतभेदों के कारण, कम से कम आने वाले कुछ सालों में, आपसी सहयोग के बाधित होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक सहयोग की ये मांग केवल सामान्य विश्वासों और मूल्यों पर आधारित नहीं है। यह एक रणनीतिक उपकरण भी है। 2022 में आगे बढ़ते हुए, डिजिटल क्षेत्र में लोकतांत्रिक सहयोग के मंचों को ऐसे बहुपक्षीय मुद्दों और प्रश्नों से निपटना होगा । सबसे पहले तो इनमें से कई लोकतांत्रिक पहल से जुड़े मंचों पर नागरिक समाज की भागीदारी जैसे विभिन्न मोर्चों पर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। जबकि इन मुद्दों के हल के कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन सबसे पहला कदम तो प्रतिनिधित्व का है। कम प्रतिनिधित्व वाले इन देशों में डिजिटल लोकतंत्र की स्थापना और उससे जुड़ी चुनौतियों पर अनुसंधान और उसके लिए निवेश के विविध स्रोत महत्त्वपूर्ण हैं। दूसरा, डिजिटल क्षेत्र की प्रकृति ऐसी है कि उसकी कार्यप्रणाली, प्रभाव और ताकत पर केवल राज्यों का नियंत्रण नहीं है । डेटा अपने मूल रूप में प्रवाहित होता है, जिसका लाभ सत्तासीन उठाते हैं । डेटा प्रवाह और संग्रहण का सबसे बड़ा फ़ायदा कुछ मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग उठाते हैं, ख़ासकर अमेरिका और चीन के बड़ी टेक कंपनियां। इसके कारण एक जायज़ डर ये उठता है कि विकासशील और अविकसित देश अतीत में हुई औद्योगिक क्रांतियों की तर्ज पर डेटा प्रदाता और उपभोक्ता के रूप में सीमित हो जायेंगे। इसलिए सार्वजनिक हित में प्रौद्योगिकियों के निर्माण, जो विभिन्न देशों और समुदायों के विशिष्ट हितों के अनुकूल हैं, के लिए स्थानीय डेटा पर स्वामित्व सुनिश्चित करने वाले तंत्रों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के संचालन से जुड़ी दो प्रकार की चिंता का पहला बिंदु ये है कि कई प्लेटफ़ॉर्म स्थानीय भाषा में संचालन के लिए संसाधनों का आवंटन इस प्रकार करते हैं, जो सांस्कृतिक बारीकियों का ध्यान रखने में असमर्थ सिद्ध होता है। दूसरी चिंता ये है कि सामग्रियों को ऐसे मानकों के अनुरूप संचालित किया जाता है, जो उपयोगकर्ता की भौगोलिक स्थिति यानी उसके देश के कानूनों से संगत नहीं होता । जिसके कारण संप्रभुता और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से जुड़े कठिन सवाल उठने लगते हैं। क्या दिग्गज टेक कंपनियों के पास ऐसे फ़ैसलों की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो संप्रभु कानूनों को चुनौती दें? उन्हें क्या करना चाहिए जब उक्त कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उनकी अपनी नीतियों के विरोध में हों? क्या बड़ी टेक कंपनियां प्रतिबंधात्मक ऑनलाइन व्यवस्थाओं के उदय को बढ़ावा देने में शामिल हैं? इसलिए, डिजिटल लोकतंत्र के संबंध में होने वाली किसी भी बहस या उसके नीतिगत विकल्पों में बड़ी टेक कंपनियां अनिवार्य रूप से शामिल हैं। (1,2,3)

डिजिटल लोकतंत्र की स्थापना के मूल आधारबिंदु क्या हैं? लोकतांत्रिक देशों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर के बड़े पैमाने पर उपयोग से एक बात स्पष्ट है कि निगरानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए स्पष्ट मापदंडों की आवश्यकता है लेकिन इसके साथ ही निजी कंपनियों द्वारा उत्पादित इन निगरानी उपकरणों को भी निरीक्षण की आवश्यकता है। आने वाले सालों में, अगर इन गतिविधियों और उत्पादों पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं किया गया तो क्वॉन्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां इन्हें बढ़ावा देंगी । डिजिटल सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के उच्चस्तरीय पैनल ने मौजूदा वक़्त को काफी महत्वपूर्ण करार दिया हैं । इसमें "अपरिचित और अनजान शिखर, बेइंतहा वायदे और हमारी पकड़ ढीली होने के ख़तरे ज़ाहिर तौर पर" सामने हैं। कोविड-19 महामारी और दुनिया भर में एक के बाद एक कई विनाशकारी सोशल मीडिया घटनाओं से ये दलील बेहद मौज़ू लगने लगी है। वैश्विक प्रशासन से जुड़े एजेंडे में पहले से ही मसलों की भरमार है। अब संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने इसमें डिजिटल सहयोग को भी शामिल करने का आह्वान किया है । सामूहिक तौर पर इस दशक में सामने आए संकटों से डिजिटल प्रौद्योगिकी की प्रमुखता स्पष्ट हो गई है। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक दायरों में ये प्रभाव ज़ाहिर है। यूक्रेन में जारी युद्ध इस सिलसिले में ख़ासतौर से अहम हो जाता है। इस जंग से डिजिटलाइज़ेशन और प्रौद्योगिकीय प्रशासन पर असर डालने वाले मसले सुर्ख़ियों में आ गए हैं। उम्मीद के मुताबिक ही सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स सूचनाओं के प्रसार, संचार और संगठन के लिहाज़ से प्रमुख मंच बनकर उभरे हैं। यूक्रेनी सरकार ने दुनिया से संवाद करने और उनसे ज़रूरी कार्रवाई की अपील करने के लिए इन माध्यमों का भरपूर इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की जनता भी प्रत्यक्ष रूप से ज़मीनी स्तर की घटनाओं का दस्तावेज़ तैयार करने और दुनिया के सामने उनका बयान करने की क़वायदों में जुटी है। (1,3,4)

इन सबके बीच प्लेटफ़ॉर्मों और टेक कंपनियों ने अभूतपूर्व क़दम उठाए हैं। उनके द्वारा नैतिक मूल्यों से जुड़े निर्णय लिए गए हैं और खुलकर कार्रवाइयां की गई हैं। उन्होंने छूट देने से लेकर नफ़रती बयानबाज़ियों पर नियम तय किए हैं। सर्च इंजनों, सॉफ़्टवेयर विक्रेताओं और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों द्वारा लिए गए इन एक-तरफ़ा फ़ैसलों की सावधानी से पड़ताल करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इन कार्रवाइयों से टेक कंपनियों के तटस्थ किरदार और महज़ सेवा प्रदाता होने की धारणा को चुनौती मिली है । निजी किरदारों के लिए इसके गंभीर मायने निकलते हैं । दुनिया की सरकारें इन प्लेटफ़ॉर्मों का जिस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं, उनसे शक्ति संतुलनों और प्रौद्योगिकीय प्रशासन में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के शक्ति प्रदर्शन से तात्कालिक रूप से कई अहम सवाल उभरकर सामने आते हैं। इस संकट को लोकतंत्र के लिए संघर्ष के तौर पर परिभाषित किया गया है। इसके बाद डिजिटल लोकतंत्र की बारी आती है और साइबर संसार में यही दांव पर लगा है। निजी किरदारों की इन निर्णायक कार्रवाइयों से सूचना से जुड़े वातावरण पर असर पड़ा है। सार्वजनिक तौर पर इसके नतीजे दूरगामी होने वाले हैं। इस संदर्भ में इन निगमों की कार्रवाइयों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़े सवाल खड़े होते हैं। ख़ासतौर से ये सवाल खड़ा होता है कि विकासशील देशों में वो कौन से फ़ैसले ले सकते हैं या दूसरे दायरों और भौगोलिक क्षेत्रों में उनके निर्णय क्या हो सकते हैं? वो किन सरकारों और क़ानूनों के प्रति जवाबदेह हैं? क्या उनके द्वारा उठाए गए क़दम लोकतंत्र की रक्षा के संकेतक हैं या फिर हमें ये मानना होगा कि डिजिटल लोकतंत्र के बचाव और उन्हें लागू करने से जुड़ी क़वायदें उन कार्रवाइयों और फ़ैसलों पर आधारित हैं जिनके पीछे की दलीलों के बारे में हमें सामूहिक रूप से पर्याप्त जानकारी नहीं है? इन कार्रवाइयों से एक बार फिर सूचनाओं के प्रवाह और डिजिटल संचार पर चंद निजी कंपनियों की बेहिसाब ताक़त का इज़हार हुआ है। इन कार्रवाइयों के पीछे झूठी और ग़लत सूचनाओं को रोकने की क़वायद मालूम होती है, लेकिन इससे ये संकेत भी मिलते हैं कि सोशल मीडिया की बड़ी कंपनियां ख़ुद ही पंच, पंचायत और सज़ा देने वाले अधिकारी बन गए हैं। वही ये तय करते हैं कि साइबर संसार में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक गतिविधियों के दायरे में क्या-क्या चीज़े आती हैं ।

इस सिलसिले में अफ़्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाइजीरिया की मिसाल ले सकते हैं। जून 2021 में वहां की सरकार ने ट्विटर पर बेमियादी पाबंदी लगा दी। दरअसल, ट्विटर ने अपनी नीतियों के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति मुहम्मदु बुहारी द्वारा किए गए एक पोस्ट को डिलीट कर दिया था। इसके बाद का घटनाक्रम आंखें खोल देने वाला है, जिनसे ये पता चलता है कि ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के निर्णयों से किस तरह के उत्प्रेरक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। प्रतिबंध के पक्ष में नाइजीरियाई सरकार की अपनी दलील थी। उसका कहना था कि ट्वीटर ने अपने प्लेटफ़ॉर्म का गलत उपयोग किया । साथ ही ट्वीटर द्वारा स्थानीय संदर्भों को नहीं समझने की दलील भी दी गई। ट्वीटर पर सात महीनों की पाबंदी ने नाइजीरियाई सरकार को वर्चुअल निजी नेटवर्कों पर भी कुछ हद तक रोकटोक की बजाए पूरी तरह से पाबंदी लगाने का मौक़ा दे दिया। इस तरह वहां की सरकार को आगे बढ़ाने लगी। इस पूरे तमाशे में नाइजीरिया की जनता फंसकर रह गई। संचार और कारोबार से जुड़े अहम साधन महीनों तक उनसे दूर हो गए । वैसे तो ट्वीटर पर पाबंदी अब हट चुकी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से नाइजीरिया की सरकार ताक़तवर बनकर उभरी है। नाइजीरिया की सरकार ने मांग रखी थी कि ट्वीटर राजधानी अबुजा में अपना स्थानीय कार्यालय खोले, स्थानीय तौर पर टैक्स अदा करे, प्रसारक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और ट्वीटर ने तमाम मांगों को चुपचाप स्वीकार कर लिया। (1,2,5)

अगर इन प्लेटफ़ॉर्मों के कर्ता-धर्ता इसी तरीक़े से काम करते रहे तो डिजिटल लोकतंत्र एक सपना बनकर रह जाएगा। इन प्लेटफ़ॉर्मों और पश्चिमी दुनिया से बाहर के देशों की सरकारों के झगड़ों से ये बात साफ़ हो चुकी है। इन प्लेटफ़ॉर्मों की सेवाएं इस्तेमाल करने वाले लोग भिन्न-भिन्न भौगोलिक हालातों, राजनीतिक-आर्थिक माहौल और पेचीदगियों में निवास करते हैं। ये प्लेटफ़ॉर्म अपने कामकाज में इन बातों की अनदेखी करते रहते हैं। ऐसे में सरकारों द्वारा इन प्लेटफ़ॉर्मों को ठप करने या उनपर पाबंदियां कायम करने के रुझान में तेज़ी आ सकती है। लेकिन क़ानूनों और नियमनों में ऐसे बदलाव से उन स्वतंत्रताओं का ही अतिक्रमण होगा जिनकी हिफ़ाज़त करने की उनसे उम्मीद रहती है।

निष्कर्ष : एक आदर्श के तौर पर डिजिटल लोकतंत्र की वैधानिकता अब सवालों के घेरे में है। इसके चलते प्रौद्योगिकीय प्रशासन में राज्यसत्ताओं की प्रतिकूल कार्रवाइयां या प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। हक़ीक़त ये है कि तमाम बड़ी कंपनियां कई घरेलू क़ानूनों के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। विश्व स्तर पर कई सरकारे डिजिटल दायरों और टेक क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों पर अपनी ताक़त का धौंस जमाने को उत्सुक हैं। ऐसे में सियासी तौर पर तनाव भरे संदर्भों में कठोर क़ानूनों और नियमनों के निर्माण और मंज़ूरी की प्रक्रिया में तेज़ी आ सकती है।

संदर्भ :

1 ननजीरा, एस 2022 : दो सूरमाओं की भिड़ंत: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर वर्चस्व, ताक़त और डिजिटल प्रजातंत्र के भविष्य का,ओ आर एफ

2 तृषा,आर 2022 डिजिटल प्रजातंत्र: रेत में खिंचती संभावनाएं और टकराव का लकीरें ,ओ आर एफ

3https://www.washingtontimes.com/news/2009/jun/16/irans-twitter-revolution

4https://demtech.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/127/2021/01/CyberTroop-Report-2020-v.2.pdf

5https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus